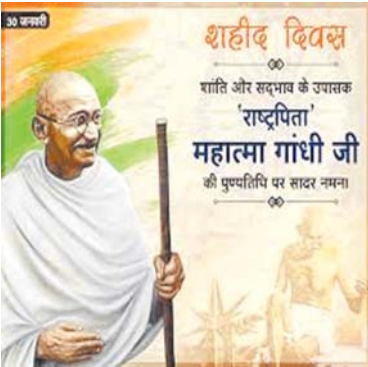




वर्ष 54/ अंक 182/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10

संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल

■ आर.एन.आई 22296/71 ■ डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

भोपाल, गुरुवार 30 जनवरी 2025 भोपाल से प्रकाशित

dainiksandhyaprakash.in



महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि राष्ट्रपति, पीएम मोदी, राहुल ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी सेवा और

बलिदान को याद करता हूँ। राहुल गांधी ने लिखा- कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह भारत की आत्मा हैं, और हर भारतीय में आज

भी जीवित हैं। सत्य, अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला सकती हैं- पूरा विश्व उनके इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है। राष्ट्रपिता, महात्मा, हमारे बापू को उनके शहीद दिवस पर शत-शत नमन।

बापू हमारे आदर्श, रोजगार के अवसर बढ़ाने जापान आया हूँ: मोहन यादव

महात्मा गांधी ने अहिंसा, स्वतंत्रता और मानवता के लिए काम किया



भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने जापान दौरे के बीच कोबे शहर में बापू को याद करते हुए कहा कि, गांधी जी ने अहिंसा, स्वतंत्रता और मानवता के लिए काम किया। बापू हमारे आदर्श हैं और प्रेरणा भर में भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको स्मरण करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मध्य प्रदेश में निवेश और युवाओं लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा पर हूँ। मध्यप्रदेश को लेकर जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि अपने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान आर्थिक संपन्नता के साथ औद्योगिक क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति में है। जापान के लोग रिसर्च को महत्व देते हैं। यह देश कई प्रकार की संभावनाओं से भरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी यह यात्रा जापान और मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित होगी।

बापू ने दुनिया भर में भारतीयों का मान-सम्मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में ठीक ही कहा था कि 'भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।' मुख्यमंत्री यादव ने कहा, 'महात्मा गांधी ने अहिंसा, स्वतंत्रता और मानवता के लिए काम किया। बापू हमारे आदर्श हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। बापू ने दुनिया भर में भारतीयों का मान-सम्मान बढ़ाया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको स्मरण करता हूँ।' मुख्यमंत्री यादव ने जापान प्रवास की चर्चा करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा पर हूँ।

सांध्यप्रकाश विशेष

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एलन मस्क का नॉमिनेशन, जानें क्यों इस यूरोपीय सांसद ने आगे बढ़ाया नाम

यूरोपीय संसद के स्लोवेनियाई सदस्य ब्रैंको ग्रिप्स ने आधिकारिक रूप से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है।



ग्रिप्स के अनुसार, यह नॉमिनेशन अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में मस्क के निरंतर प्रयासों और वैश्विक शांति में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। ब्रैंको ग्रिप्स ने इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा, '%आज सफलतापूर्वक यह प्रस्ताव पेश किया गया कि एलन मस्क, जो लगातार अभिव्यक्ति की

मुंबई में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर बैन की तैयारी, जल्द लागू हो सकता है नया कानून...

महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और इसे अधिक ग्रीन और क्लीन बनाना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो मुंबई में केवल इलेक्ट्रिक (थ्रू) और एलईवी वाहन ही संचालित हो सकेंगे। सरकार ने इस विषय पर अध्ययन करने के लिए एक सात सदस्यीय समिति गठित की है, जो तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।



रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एचएआई) 2020 से अब तक 12वें तक खराब हो चुकी है, और इसका प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, अत्यधिक ट्रैफिक जाम, निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रदूषण है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाने की संभावनाओं पर विचार करे। इसके जवाब में, 22 जनवरी को सरकार ने एक संयुक्त प्रस्ताव का गठन किया, जो इस योजना के प्रभावों और व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

हालांकि, इस प्रतिबंध से बेहतर वायु गुणवत्ता और कम प्रदूषण की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। मुंबई में अभी भी पर्याप्त थ्रू चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी तरह से निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, शहर की मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भर लाखों लोगों के लिए यह एक चुनौती बन सकता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सर्विस और टैक्सी उद्योगों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूल-चालित वाहनों को बदलने में उन्हें भारी लागत का सामना करना पड़ेगा।

बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की।



पन्ना में जेके सीमेंट प्लांट में हादसा 5 की मौत, 30 मजदूर घायल



पन्ना। पन्ना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में निर्माणार्थन हिस्से में छत की स्लेब डाली जा रही थी, जहां संकेदों मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भाड़ा (स्केफोल्डिंग) गिर गया, जिसकी चोट में आने से 5 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 मजदूर घायल हुए हैं। कंपनी के सूत्रों ने बताया कि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। राहत

और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एम्बुलेंस भी मौके पर हैं, हालांकि अब तक घायल मजदूरों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया है। वहीं, मलबे में दबे कई मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए फेक्ट्री के अंदर प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक मृतकों और घायलों की सटीक संख्या की प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गया है।

सिवनी सीएमओ के यहां ईओडब्ल्यू का छापा

छिंदवाड़ा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) टीम ने गुरुवार सुबह सिवनी नगर पालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमओ) और बालाघाट की प्रभारी दिशा डेहरिया के नागपुर रोड स्थित आवास पर छापेमारी की। छिंदवाड़ा के अलावा उनके सिवनी और बालाघाट के घर पर रेड जारी है।



आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद जबलपुर से आई ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 6-30 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जांच शुरू की। सुरक्षा कारणों से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मकान के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। ईओडब्ल्यू की 12 लोगों की टीम सर्चिंग कर रही है, इसे ईओडब्ल्यू डीएसपी स्वर्णजीत सिंह धामी लीड कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू की टीम प्रॉपर्टी का वेल्थएशन में जुटी है। वहीं दूसरी टीम दिशा डेहरिया को सिवनी से लेकर वारासिवनी (बालाघाट) के लिए रवाना हुई है।

जगदंबिका पाल ने वक्तव्य संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। इससे पहले समिति ने बुधवार को 655 पेज वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों की ओर दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका



आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। इसके उलट भाजपा सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में

पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, महाकुंभ में भगदड़ के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग महाकुंभ में भगदड़ से 30 लोगों की मौत, सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में सभी राज्यों को निर्देश देने की अपील की गई है कि वे प्रयागराज में अपने सुविधा केंद्रों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा,



विभिन्न भाषाओं में घोषणाओं, दिशानिर्देशों और मार्गदर्शक डिस्के बोर्डों की स्थापना की भी मांग की गई है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर सभी राज्य सरकारें महाकुंभ में चिकित्सा आपातकाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों की मेडिकल टीम तैनात करें, जिससे मेडिकल स्टाफ की कमी न हो और त्वरित इलाज संभव हो सके।

दूध में शक्कर की तरह हर जगह एडजेस्ट होने की कला है भारतीयों में: डॉ. मोहन यादव

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतवंशी अपनी परिवार परंपरा से जहां काम करते हैं वहां निष्ठा का भाव रखते हैं। यही कारण है कि वे हर जगह एडजेस्ट हो जाते हैं। एडजेस्ट भी ऐसे जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चार दिवसीय जापान यात्रा के दूसरे दिन जापान में भारतवंशियों फ्रैंड्स ऑफ एम.पी. को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन, ऑटो मोबाइल, टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं रेडिमेड गारमेंट के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर जापान में भारत के राजदूत सी.व्ही. जार्ज, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

एक होते हैं सगे, एक होते हैं संबंधी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम भारतवंशी ही सगे संबंधियों की समझ सकते हैं। विदेश प्रवास के दौरान भी आप लोगों को सामने देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सगे-संबंधियों के बीच आ गए हैं। हमारे देश में कोई भी उत्सव या समारोह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उस समारोह में सगे- संबंधियों की उपस्थित न हो। मैं आपको म.प्र. में फरवरी में होने जा रहे औद्योगिक निवेश के भव्य समारोह जीआईएस के लिये आमंत्रित करने आया हूँ। विदेश में अनजान चेहरों के बीच जब हमवतन दिखाई देते हैं तो भारतीयता की विशेष



अनुभूति होती है।

प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हमारी संस्कृति: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो की भावना को सर्वोपरि रखकर काम करते हैं और यही वजह है कि हिन्दुस्तानी आपको हर देश में हर काम को निष्ठा के साथ करता हुआ मिल जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने इकबाल के शेर का जिक्र भी किया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी... हम हर कठिनाई, हर चुनौती को

मात देकर आगे बढ़ पाते हैं, यह हमारी विशेषता है।

हम आगे बढ़ना चाहते हैं: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति रही है कि कभी हमने आक्रमण नहीं किया, कभी किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें विश्व गुरु के मार्ग पर आगे चलना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयामों को छुआ है। मैं कह सकता हूँ कि नेता तो पहले भी आते जाते रहे होंगे परंतु लोगों के मन में प्रधानमंत्री श्री मोदी के आगमन और

विदेशी मंच पर उनके सम्मान को देखते हुए जिस विश्वास और दृढ़ता का भाव पैदा होता है, उस भाव से मन में गर्व की अनुभूति होती है।

मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा देश का आत्म-विश्वास: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जापान में बसे भारतवंशियों और फ्रैंड्स ऑफ एमपी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने कोविड काल की चुनौतियों से पार पाने की सफलता का मन उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी के

नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व से विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है और हमारी उपस्थिति सम्मानजनक बनी है, साथ ही भारतवंशियों का आत्म-विश्वास भी बढ़ गया है।

सदेच्छा से संकल्प सिद्धि

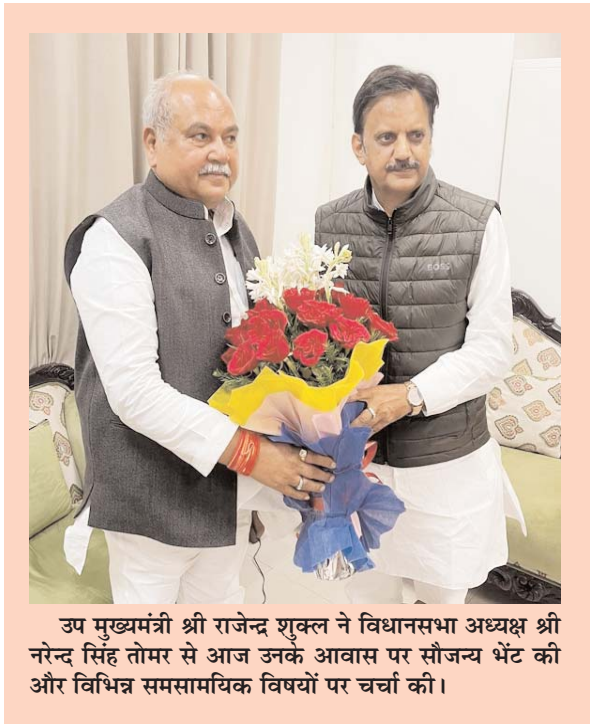
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति उदात्त है, हम सदैव विश्व के कल्याण की बात करते हैं, भारतवंशी जहां भी रहते हैं वहीं के कल्याण में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा करने का संकल्प और हमारी सभी के प्रति सदेच्छा हमारी कार्यसिद्धि का साधन बन जाते हैं।

उगते सूरज का देश है जापान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जापान उगते सूरज का देश है। भारत और जापान के राष्ट्र ध्वज की समानता को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि जापान के ध्वज के मध्य में उगते सूरज को चिन्हित किया गया है, वहीं भारत के ध्वज के मध्य 24 चक्र 24घंटे विकास को इंगित करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां 50 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। मैं उन सभी भारतवासियों से कह रहा हूँ कि जो यहां काम कर रहे हैं, जापान के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करते रहें। उन्होंने कहा कि कई देश भारत की परिवार और कुटुम्ब परम्परा को नहीं समझते। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की एकता का आधार है।

प्रधानमंत्री की थाली और ताली की भाषा को सारे देश ने समझा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व ही था जब कोरोना महामारी के काल में उन्होंने थाली और ताली बजवाकर कोरोना की गंभीर प्रवृत्ति का लोगों को आभास कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे आर्यडियल और अग्रणी नेता हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की रफ्तार को लोकडायन के माध्यम से नियंत्रित कर देशवासियों को सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे समृद्ध और विकसित देश कम मैनपावर के बावजूद अपनी देश प्रेम की भावना और मेहनत के बल पर दुनिया के आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और समृद्ध देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हम आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों की पंक्ति में पांचवें स्थान पर हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा ने कहा कि विगत एक वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक विकास के नवाचार किए और नए आयाम स्थापित किए हैं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वे रीजनल इन्व्स्टीज की अवधारणा को धरातल पर लेकर आए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा कर निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहक श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने फ्रैंड्स ऑफ मध्यप्रदेश के बीच मध्यप्रदेश गाउन सूचू का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है- मां की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है की पंक्तियों के साथ जापान में बसे भारतवासियों को अपने देश और प्रदेश की मिट्टी की याद दिलाई।



उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से आज उनके आवास पर सौजन्य भेंट की और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की।

महाराज अग्रसेन की 11वीं महाआरती 2 फरवरी को

भोपाल। अग्रकुल प्रवर्तक एवं अग्रवाल समाज के आराध्य देव भगवान महाराज अग्रसेन और कुलदेवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भोपाल में माह के प्रथम रविवार को महाआरती की जा रही है। ग्यारहवीं महा आरती का आयोजन रविवार, 2 फरवरी 2025 समय - सायं 5 बजे, महाराज अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष, आईटीसी पार्क, कमला पार्क के सामने, भोपाल में की जा रही है।



आरजीवीवी कर्मचारियों ने कुल सचिव कक्ष के सामने किया प्रदर्शन



भोपाल। आर जी व्ही वी के स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने आज अपनी सात सूत्रीय मांगों के समर्थन में कुल सचिव मोहन सेन के कक्ष के समक्ष जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया प्रदर्शन में अमर अहिर् जगदीश शर्मा शाजली इजहार आदि दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि आर जी व्ही वी के कर्मचारियों की सात सूत्रीय मांगे लंबे समय से लंबित है मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से चरणबद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन मांगों को संज्ञान में नहीं ले रहा है कुल सचिव ने लिखित में आश्वासन देने के बाद भी मांगों पर आदेश जारी नहीं करें हैं जिस कारण

विश्वविद्यालय के समस्त स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है कुल सचिव ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ देने के लिए 7 सदस्य वाली कमेटी का गठन कर दिया है कमेटी की बैठक भी हो चुकी है मांगों के प्रस्ताव भी तैयार करके कुल सचिव को अनुमोदन हेतु भेज दिए गए हैं लेकिन मुख्य आदेश अभी नहीं जारी हुए मांगे प्रमुख रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थाई कर्मी बनाने स्थाई कर्मियों को नियमित करने आउट सोर्स प्रथा समाप्त करने स्थाई कर्मियों को शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश सुविधा का लाभ देने पीएफ सुविधा बीमा सुविधा मेडिकल सुविधा का लाभ देने आदि है।

राज्यमंत्री बागरी ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास तथा डिंडोरी जिले की प्रभारी राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की मंत्रालय स्थित कक्ष में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम के अधिकारियों से डिंडोरी, करंजिया और शहपुरा-मेहदवानी समूह जल प्रदाय परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने परियोजनाओं की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक मैनपावर और संसाधनों का समुचित उपयोग कर कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे योजनाओं का शीघ्र लाभ आमजन तक पहुंच सके। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित स्थानों का रिस्टोरेशन कार्य भी प्रभावी ढंग से किया जाए, जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने अधिकारियों को जल मिशन के कार्यों को तत्परता से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि नल-जल योजना का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाये। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने कहा कि फरवरी माह में वे स्वयं परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करेंगी। एक महान देश का पर्यटन की दृष्टि से दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा देश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध है। राज्यमंत्री श्री लोधी बर्सिलोना स्पेन में पर्यटन के रोड-शो कार्यक्रम में दूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट्स, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित कर

गया कि यात्रा के दौरान किसी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा होने पर उसके द्वारा पैनिक बटन दबाने पर संदेश क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के राज्य स्तरीय कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर पर प्रेषित हो जाता है। संदेश की आधार पर वाहन की वास्तविक लोकेशन ट्रेक की जाकर उसे त्वरित सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में अब तक करीब 60 हजार वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग



शहीदों की स्मृति में रखा गया मौन

भोपाल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में संभागायुक्त कार्यालय परिसर में दो मिनट का मौन धारण किया गया। संयुक्त आयुक्त विनोद यादव सहित कार्यालय में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

राष्ट्र के विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका : राज्य मंत्री लोधी

भोपाल। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि राष्ट्र के विकास और प्रगति में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे महान देश का पर्यटन की दृष्टि से दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा देश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध है। राज्यमंत्री श्री लोधी बर्सिलोना स्पेन में पर्यटन के रोड-शो कार्यक्रम में दूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट्स, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित कर

राष्ट्र के विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका : राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि मैं पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश और प्रदेश भारत के मध्य में स्थित प्रांत देश के हृदय निरंतर उच्च मापदंडों को स्पर्श कर रहा है।

प्रदेश मध्यप्रदेश से हैं। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि जिस तरह हृदय सम्पूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करता है, उसी तरह भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक संस्कृति का मार्ग भी मध्यप्रदेश से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हमारी संस्कृति दुनिया की एक मात्र संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुम्बक की बात करती है, सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार मानती है। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि हमारी संस्कृति न केवल मानव जाति के कल्याण की, अपितु बल्कि सम्पूर्ण जगत के कल्याण की बात करती है। हमने आज भी अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों को न केवल अक्षुण्न रखा है, बल्कि उसे सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित भी किया है।

सम्पादकीय

सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों और लोक अभियोजकों की राजनीतिक आधार पर नियुक्ति करने की प्रवृत्ति पर बुधवार को गहरी चिंता व्यक्त की। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि भाई–भतीजावाद और फेवरिज्म को ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

देखा जाए तो यह फैसला सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील और सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह नियुक्त व्यक्ति की योग्यता, उसकी कानूनी दक्षता, उसकी पृष्ठभूमि और उसकी ईमानदारी की जांच करे।



असल में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक आपराधिक अपील के दौरान लोक अभियोजक की कमजोर पैरवी को देखकर की, जिससे आरोपी को सजा दे दी गई थी। कोर्ट यह देखकर चौंक गया कि हाई कोर्ट ने एक रिवीजन याचिका में ट्रायल कोर्ट के बरी के फैसले को पलट दिया, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। रिवीजन याचिका का माध्यम से बरी किए गए व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिక్यूटर ने इस कानूनी त्रुटि को बताने के बजाय आरोपी को मौत की सजा देने की मांग कर दी, जबकि राज्य सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील ही दायर नहीं की थी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अफसोस जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट में लोक अभियोजकों के स्तर का ये हाल है। अदालत ने कहा कि लोक अभियोजक एक सार्वजनिक पदाधिकारी होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उसे कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं। लोक अभियोजक किसी जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्र पदाधिकारी होता है। लोक अभियोजक को न्यायिक प्रणाली में अपराध के अभियोजन की ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तीन अपीलकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 5–5 लाख रुपये देने का आदेश दिया, जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता उचित ही है, क्योंकि सामान्य तौर पर सरकारी वकील बनाने की प्रक्रिया एक जैसी रहती है। जिस दल की सरकार होती है, उस पार्टी के सदस्य वकीलों को ही सरकारी वकील नामित कर दिया जाता है। सरकारी वकील और नोटरी का पंजीयन सरकारें दलीय आधार पर ही करती हैं। इसी के चलते विरोधी पार्टियों के लोगों को सामान्य मामलों में भी सजा कराने का दबाव बनाया जाता है और अपनी पार्टी के लोगों को गंभीर मामलों में भी बरी कराने की कोशिश की जाती है। निचली अदालतों में तो सरकारी वकील सामान्य तौर पर न्यायाधीशों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं।

सही मायने में अदालतों में नियुक्त किये जाने वाले सरकारी वकील पूरी तरह से सरकारी ही होते हैं। राजनीति से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। शासन नहीं, सत्ता में कौबिज पार्टी की तरफ से ही अदालत में खड़े होते हैं और एक पार्टी विशेष की ही पैरवी करते दिखते हैं। यही कारण है कि जिस पार्टी की सरकार आती है, वह पुराने वकीलों को बदल कर अपनी पार्टी के लोगों को सरकारी वकील का चोला पहना देती है। यही कारण है कि अदालतों पर से भरोसा उठता चला जाता है।

कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता तो वाजिब है, लेकिन सरकारें इस चिंता से सहमत हो भी पायेंगी या नहीं। सरकारों की जिस तरह से कार्यप्रणाली बदल रही है, वह कहीं से भी निरपेक्ष नहीं रह गई है। वह जनता के बजाय एक पार्टी की सरकार बन जाती है और उसी पार्टी के लिए समर्पित होकर रह हाती है। ऐसे में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया और सोच पर समालिया निशान लगना स्वाभाविक ही है। और सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद भी लगता नहीं कि इसमें कुछ बदलाव या सुधार हो पायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट से मिल सकती हैं कई सौगतेें

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2024–25 की पहली छमाही (अप्रैल–सितम्बर 2024) में भारत की आर्थिक विकास दर कुछ कमजोर रही है। प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून 2024) में तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इसी प्रकार द्वितीय तिमाही (जुलाई–सितम्बर 2024) में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में मुख्य रूप से देश में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव है और आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भरकम कमी दुष्टिगोचर हुई है। साथ ही, देश में मानसून की स्थिति भी ठीक नहीं रही है।

केंद्र सरकार ने हालांकि मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने में सफलता तो अर्जित कर ली है परंतु उच्च स्तर पर बनी रही मुद्रा स्फीति के कारण कुल मिलाकर आम नागरिकों, विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों, की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है और कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की श्रेणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रहती है, उस देश की आर्थिक विकास दर ऊंचे स्तर पर बनी रहती है क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए फ्लेट्स एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग करता है। इससे आर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं।

भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय

परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है अतः दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे वित्तीय वर्ष 2025–26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि न केवल आय कर में बल्कि कारपोरेट कर में भी कमी की घोषणा की जानी चाहिए।

इनफोसिस के संस्थापक सदस्यों में शामिल श्री मोहनदास पई का तो कहना है कि 15 लाख से अधिक की आय पर लागू 30 प्रतिशत की आय कर की दर को अब 18 लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। आय कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में लागू 7.75 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देना चाहिए। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत किए जाने निवेश की सीमा को भी 1.50 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रदान की जाने वाली आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए।

फरवरी 2025 माह में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पोलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे रेपो दर में कम से कम 25 अथवा 50 आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि, पिछले लगातार लगभग 24 माह तक रेपो दर में कोई भी परिवर्तन नहीं करने के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं चार पहिया वाहन आदि खरीदने हेतु बैंकों से लिए गए ऋण की किश्त की राशि का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। बैंकों से लिए गए इस प्रकार के ऋणों एवं माइक्रो फाइनेन्स की किश्तों की अदायगी में चूक की

घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुद्रा स्फीति की दर खाद्य पदार्थों (फलों एवं सब्जियों आदि) के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर पर आ जाती है जबकि कोर मुद्रा स्फीति की दर तो अब नियंत्रण में आ चुकी है। खाद्य पदार्थों की महंगाई को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक को अब इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम तिमाही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते देश में पूंजीगत खर्चों में कमी दिखाई दी है। इसीलिए अब लगातार यह मांग की जा रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के चलते अपने बजटीय खर्चों को रोक दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लोक सभा में पेश किए जाने वाले बजट में पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर गम्भीरता दिखाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 7.50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे देश में धीमी पड़ रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे, जिसकी वर्तमान समय में देश को अत्यधिक आवश्यकता भी है।

विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही फ्रीबीज की योजनाओं पर भी अब अंकुश लगाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन योजनाओं से देश के आर्थिक

दिल्ली चुनाव का यह आयाम

कुछ उपकर ऐसे हैं, जो देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी को चुकाने ही पड़ते हैं।

इनमें आम आदमी भी शामिल है, लेकिन मध्य-वर्ग ऐसा है, जिसे निचोड़ा जाता रहा है, लेकिन बदले में वह ‘रेवडिड्यो’ की अपेक्षा भी नहीं करता। वह मुफ्तखोरी का पक्षधर नहीं है। अरबपति उद्योगपतियों का एक खास वर्ग है, जिसे किसी भी पार्टी की सत्ता

पाल-पोस कर रखती है। इस वर्ग के 14.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज बैंकों की ‘बट्टे खाते’ (राइट ऑफ़) में डालने ही पड़ते हैं। एक अरबपति को 6500 करोड़ रुपए का कर्ज मिला, लेकिन जब यह मामला आपस में सैटल किया गया, तो अरबपति को 1500 करोड़ रुपए का ही भुगतान करना पड़ा। देश में 400–500 ‘औद्योगिक मित्र’

गांवों की खुशहाली मापने के लिए बनाएं नए मानदंड

जिन परिवारों के पास सहूलियतें बहीं, उन परिवारों ने अपनी हैसियत और बजट के लिहाज से मुफ्ति पाए जाने वाले शहरों की ओर रहने के लिए रुख किया। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण आबादी का जो अनुपात आबादी के समय था, वह आज बदल चुका है। आजादी के वक्त तकरीबन 80 फीसद से ज्यादा लोग गांवों में रहते थे, अनुमान है कि वह घटते-घटते अब साठ और पैंसठ फीसद के बीच आ गई है।

रिर्कार्ड पर ग्रामीण आबादी का इतना बड़ा हिस्सा भले ही गांवों में बसता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में रोजी–रोटी और शिक्षा के लिए कभी शौकिया तो कभी मजबूरीवश रहने को मजबूर है। इसलिए रिर्कार्ड की तुलना में वास्तविक ग्रामीण आबादी अब और भी कम हो चुकी है।

घरेलू खर्च के इस नए आंकड़े को देखते वक्त हमें इस संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल हमें भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में निजी या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त खाद्यान्न योजना समेत कई अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के जरिये मुफ्त में मिल रही चीजों की कीमतों को ध्यान में रखें तो घरेलू खर्च के ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4,247 रुपये और 7,078 रुपये हो जाते हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च पर औसत आठ और नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2011–12 में शहरी और खपत खर्च के बीच 84 प्रतिशत का अंतर था, जो 2022–23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया। जो अब 70 फीसद ही रह गया है। इन आंकड़ों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खुशहाली की तस्वीर सामने आती है। दिलचस्प यह है कि इस आंकड़े में खाने–पीने के अलावा की चीजों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च 60 और 53 प्रतिशत रहा। इसका मतलब साफ है कि अब



विकास को लाभ कम और नुकसान अधिक होता है। केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली की स्थिति हम सबके सामने है। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने के कारण इन राज्यों के बजटीय घाटे की स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। पंजाब तो किसी समय पर देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में शामिल हुआ करता था परंतु आज पंजाब में बजटीय घाटा भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिससे ये राज्य आज पूंजीगत खर्चों पर अधिक राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की न तो आय बढ़ रही है और न ही बजटीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है।

पिछले कुछ समय से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। यह सितम्बर 2020 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत था जो अब गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में इस विषय पर भी अवसरता से विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019 के बजट में कोरपोरेट कर की दरों में कमी की घोषणा की गई थी, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पड़ा था और सितम्बर 2020 में तो यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब एक बार पुनः इस बजट में कोरपोरेट कर में कमी करने पर भी विचार किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। हां, साथ में तकनीकी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमारे उद्योगों को हमें प्रतिस्पर्धी बनाना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है अतः कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान इस बजट के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही निर्मित हों और नागरिकों के शहर की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।

ऐसे हैं, जिनके 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने माफ करा दिया। बेशक यह वर्ग भी मतदाता है, लेकिन यह वर्ग सरकारें संचालित करता है। सरकार से सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता है कि वह उसके मोटे कर्जों को ‘बट्टे खाते’ में डलवाती रहे अथवा हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के बदले उसे कुछ सौ करोड़ रुपए ही चुकता करने पड़ें। मध्य–वर्ग में भी अपर, अर्ध अपर, मिडिल और लोअर वर्ग हैं। उनका मूल्यांकन उनके वेतन के आधार पर किया जाता है, क्योंकि आयकर भी उसी के अनुसार तय होता है। मध्य–वर्ग ऐसा है, जो गेहूं के साथ चुन की तरह पिस्ता रहा है। हालांकि यह वर्ग परिभाषित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दिल्ली में करीब 67 प्रतिशत आबादी मध्य–वर्ग के दिग्दर् में आती है। देश में औसतन 31 प्रतिशत मध्य–वर्ग माना जाता है। बहरहाल यह मुद्दा दिल्ली के चुनाव को दिशा और दशा मोड़ भी सकता है।

वस्तुओं का बड़ा योगदान है। भारत में आबादी बढ़ाने की जगह आबादी के समन्वित और संतुलित विवरण की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में आबादी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा और रोजगार गांवों या उसके आसपास ही उपलब्ध कराने की नीतियों पर अगर बहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आबादी को संतुलित किया जा सकेगा। तब गांव आबादी वहीन नहीं होंगे और शहरों पर आबादी का असंतुलित बोझ नहीं बढ़ेगा।

गांवों में हो रही खपत और खर्च को लेकर आ रहे आंकड़ों का पहला असर यही होना चाहिए कि गांवों में आबादी रुके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाके में बढ़ते खर्च से अब्वल तो गांवों में रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। लेकिन इस दिशा में ठोस बदलाव होते नजर नहीं आ रहे। बेशक आज आजादी के बाद के दौर की तरह के बदहाल गांव नहीं हैं। बेशक शहरों जितना उसे बिजली नहीं मिलती, लेकिन पहले की तुलना में अब गांवों को भी बिजली ज्यादा मिल रही है। गांवों में भी उपभोक्ता वस्तुएं पहुंची हैं। इससे बेशक पारंपरिक संस्कृति चोट भले ही पहुंची हो। यह भी सच है कि ग्रामीण विकास और दूसरी कल्याण योजनाओं के जरिए गांवों में केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से पैसा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर पर खर्च होने की बजाय नौकरशाही और राजनीतिक रिश्तव के रूप में शहरी इलाकों में ही रूक रहा है और वहीं निवेशित हो रहा है।

इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखनी चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ घरेलू खर्च के जरिए ही गांवों की खुशहाली और समृद्धि की खोज करना उचित नहीं होगा। यह तभी होगा, जब गांवों की खुशहाली और समृद्धि मापने के लिए समन्वित और समावेशी मूल्यांकन प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी ग्रामीण आबादी को मजबूरी में गांव पीछे छोड़ना पड़ा है और कितनी आबादी गांव लौट रही है। गांवों के लिए ऐसी समन्वित नीतियां तैयार करना और उन्हें लागू करना होगा, जिनके जरिए परंपरा भी बची रहे, संस्कृति की धारा भी अजस्थ बनी रहे, समृद्धि भी आए और गांवों को शहरों का मोहताज नहीं होना पड़े, जैसा महात्मा गांधी चाहते थे।

^[1] स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक — संजय सक्सेना,

^[2] प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 घ.प्र.।ई-मेल : dsdpbl67@gmail.com, वेबसाइट: dainiksandhyaprakash.in

रीन्यू ने कुम्भ में बांट कर 1 मिलियन कंबल बांट कर गिफ्ट वार्मथ कैपेन के 10वें संस्करण का सफल समापन किया

नई दिल्ली, एजेंसी। अग्रणी विकासो्नीकरण समाधान कंपनी रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने अपने सालाना कैपेन ‘गिफ्ट वार्मथ’ के 10वें संस्करण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है। रीन्यू ने 2015 में इस पहल की शुरुआत के बाद 1 मिलियन कंबल बांटने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुम्भ मेले के दौरान कंबल का आखिरी बैच वितरित कर कंपनी ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस साल रीन्यू ने प्रमुख क्षेत्रों में 200,000 से अधिक कंबल बांटें, जिसमें से मध्य प्रदेश में 22000 से अधिक कम्बल कैबिनेट मंत्री इन्दर सिंह परमार और रतलाम से विधायक मथुरा लाल दामोर द्वारा उज्जैन और रतलाम में बांटे गए। बाकी राज्यों में राजस्थान, एनसीआर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड शामिल रहे। हाल ही में कुम्भ मेले के दौरान 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार में ओद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई एवं निवेश संवर्धन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के हाथों कंबल बंटवाकर कंपनी एक मिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गई है।

इन्फिनित्स ने सबसे इयूरेबल स्मार्टफोन स्मार्ट 9 एचडी पेश किया

मुंबई, एजेंसी। नए युग के स्मार्टफोन ब्रांड, इन्फिनित्स ने अपना नया स्मार्टफोन, स्मार्ट 9एचडी पेश किया है। इस अत्याधुनिक डिवाइस में ड्युरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और स्टाइल के साथ बेजोड़ यूजर अनुभव प्राप्त होता है। यह अपनी विशेषताओं के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। इन्फिनित्स के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन का मूल्य 6699 रुपये है और यह चार आकर्षक रंगों – मिंट ग्रीन, कोरल गोल्ड, नियो टाईटैनियम, और मैटलिक ब्लैक में उपलब्ध है। यह 4 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर मिलना शुरू होगा। स्मार्ट 9एचडी में मल्टी–लेयर्ड ग्लास फिनिश बैक के साथ बहुत आकर्षक डिजाईन दिया गया है, जो एंटीफिंगरप्रिंट एवं बहुत मजबूत है। अपनी फ्लैट एज और कलर–मैचड फ्रेम के साथ यह डिवाइस प्रीमियम फील प्रदान करती है।

भारतीय मौसम विभाग और 1वेदर ने देश में 235 मिलियन लोगों को उपलब्ध कराएगी मौसम संबंधी अलर्ट

बैंगलोर, एजेंसी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और इनमोबी के वैश्विक स्तर पर अग्रणी मौसम की जानकारी देने वाले ऐप, 1वेदर ने लाखों भारतीयों को उनके ग्लांस–एनेबल्ड स्मार्टफोन लॉक स्क्रीन पर राष्ट्रीय मौसम संबंधी चेतावनी और अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए एक अनूठी रणनीतिक साझेदारी की है। आईएमडी और इनमोबी के बीच समझौता पत्र (एलओए) 235 मिलियन भारतीय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को अपने फोन को अनलॉक किए बिना, तुरंत मौसम स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह विशिष्ट अनुभव न केवल नागरिकों को सुरक्षित और तैयार रहने में मदद करेगा, बल्कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान बड़े पैमाने पर त्वरित कार्रवाई की सुविधा भी प्रदान करेगा।

द वन एंड ओनली—एक प्रतिष्ठित और फैशनबल दुनिया का प्रवेश द्वार

मुंबई, एजेंसी। ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर ने अब तक के अपने सबसे प्रतिष्ठित संस्करण का अनावरण किया है, जिससे द वन एंड ओनलीदुनिया की रचना होती है, जहां फैशन केवल एक शुरुआत है। टूर का 2025 संस्करण एक अत्याधुनिक अवतार प्रस्तुत करेगा, जो असाधारणता की सीमाओं को पार करेगा और वैश्विक फैशन, संगीत और मनोरंजन के शानदार प्रदर्शन लेकर आएगा, जो पूर्ण विस्मय से भर देंगे। फैशन डिजाइन कार्डसिल ऑफ इंडिया के साथ एक बार फिर जुड़ते हुए, फैशन टूर अपनी ग्लैमरस और भव्य पहचान का जश्न मनाएगा। इसमें भारत के सबसे चर्चित फैशन विशेषज्ञों के साथ–साथ देश के सबसे आकर्षक स्टाइल आइकन्स भी शामिल होंगे, जो निश्चित रूप से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे।हर शहर में, यह टूर अलग–अलग कहानियां रचेगा, जो इसकी प्रतिष्ठित दुनिया की अनूठी व्याख्याओं को प्रदर्शित करेगी।

‘शार्क टैंक इंडिया 4’ में दिखा आरबीडी मशीन टूल्स का प्रेरणादायक सफर

मुंबई, एजेंसी। खेती अगर ज्यादा आसान, अधिक कुशल एवं फायदेमंद हो जाए तो आरबीडी मशीन टूल्स को लाने के पीछे यही सोच है। यह नई पहल करने वाला एक स्टार्टअप है, जो भारत में खेती में बड़ा बदलाव ला रहा है। राजस्थान के एक छोटे–से गांव के देवेन्द्र कुमार टेलर और भूपेन्द्र कुमार टेलर द्वारा स्थापित इस कंपनी का लक्ष्य किसानों को नये–नये टूल्स तथा टेक्नोलॉजी से सशक्त करना है। ग्राहक को सबसे अधिक महत्व देने के नजरिये के साथ, आरबीडी मशीन टूल्स गुणवत्ता एवं किफायत के साथ ही किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।

पुलिस एसआई के 800 पदों को भरे जाने की योजना,भर्ती में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी, 7 साल से नहीं निकली वेकेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में नियमों में हाल ही में संशोधन कर युवाओं के मन में इस पद पर नौकरी की आस राज्य शासन ने भले ही जगा दी हो, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले पांच साल में कई बार उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए कई प्रस्ताव गृह विभाग तक पहुंचे, लेकिन बैरंग ही वापस पुलिस मुख्यालय तक आ गए।

नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन हाल ही में गृह विभाग के पास पुलिस मुख्यालय से कोई नया प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। सूर्यों की मानी जाए तो पुलिस मुख्यालय में उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अब नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है। जिसमें करीब 800 पदों को भरे जाने के लिए इतने पद पर भर्ती करने की योजना पुलिस मुख्यालय के चयन शाखा की है। दरअसल प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षकों की आखिरी भर्ती 2017 में हुई थी, जो वर्ष 2016 की भर्ती थी। इसके बाद से अब तक उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रदेश पुलिस में नहीं हो सकी है। वहीं सीधी भर्ती के



उपनिरीक्षकों के पद लगातार खाली होते जा रहे हैं। जिन्हें पुलिस मुख्यालय ने सहायक उपनिरीक्षकों को वन टर्म पदोन्नति देकर कार्यवाहक उपनिरीक्षक बना दिया था। इसके बाद भी उपनिरीक्षकों के कई पद

प्रस्ताव नहीं बना। इसके बाद दो साल से फिर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी गई।

अब नहीं बच पाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले! आधार से लिंक होंगे वाहन आरसी और डीएल, चालान भुगतान अनिवार्य

अब आधार लिंकिंग से इस समस्या का समाधान करने की योजना बनाई जा रही है।

नई दिल्ली। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान भरने से बचने के लिए मोबाइल नंबर या पता बदलते हैं, तो अब यह तरीका काम नहीं करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राम्रह्म॥) जल्द ही वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (ऋष्ट) और ड्राइविंग लाइसेंस (छरू) को आधार से लिंक करने का नया नियम लागू करने जा रहा है। इस फैसले से चालान कटने पर वाहन मालिक और चालक का सही पता आसानी से मिल सकेगा, जिससे जुर्माने की वसूली में तेजी आएगी।

वयों जरूरी हो रहा यह नियम?

मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रहा है ताकि सड़क पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के ई-चालान लंबित हैं क्योंकि वाहन मालिकों की जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं की गई है।



कैबिनेट ने ईएसवाई 2024-25 के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य संशोधित करने की मंजूरी दी

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी है।

यह अवधि 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगी। संशोधित मूल्य निर्धारण तंत्र के तहत, सी हेवी शीरा (ष्टाऱू) से प्राप्त इथेनॉल का नियंत्रित एक्स-मिल मूल्य बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 56.58 रुपये प्रति लीटर था।

इस संशोधन का उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्रदान करना और इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, सरकार जीएसटी और परिवहन शुल्क को अलग से वहन करना जारी रखेगी, जिससे गन्ना किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।

इस नियम से कई महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार सक्रिय रूप से ईबीपी कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसके तहत ओएमसी इथेनॉल को 20ब तक पेट्रोल में मिलाती हैं, यह कदम वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन के उपयोग को समर्थन देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को लाभ

पहुंचाने में मदद करता है।

पिछले एक दशक में, इथेनॉल मिश्रण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे महत्वपूर्ण बचत हुई है। 31 दिसंबर 2024 तक, ईबीपी कार्यक्रम ने 1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक की



विदेशी मुद्रा की बचत की है और लगभग 193 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के प्रतिस्थापन में योगदान दिया है।

ईएसवाई 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 707 करोड़ लीटर हो गया है, जिससे औसत मिश्रण दर 14.60ब तक पहुंच गई है। सरकार ने 2030 के बजाय ईएसवाई 2025-26 तक 20ब इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई है और ईएसवाई 2024-25 में 18ब मिश्रण दर प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं।

इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, इथेनॉल आसवन क्षमता को 1,713 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक बढ़ाने, समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के लिए दीर्घकालिक खरीद समझौतों की सुविधा प्रदान करने, बहु-ईंधन डिस्टिलरी को प्रोत्साहित करने और ई-100 और ई-20 ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा

देने जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

इसके अलावा, फ्लेक्सी-प्प्यूल वाहनों की शुरुआत से इथेनॉल अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है। ईबीपी कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण निवेश के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड डिस्टिलरी की स्थापना, भंडारण और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिससे घरेलू इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इन प्रगतिशील कदमों के साथ, सरकार इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और सतत और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्पों के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निजी संघर्ष से लेकर अभिनव साँल्यूशन तक: अशवाकी फाउंडर अनमोल सवसेना का सफर

मुंबई, एजेंसी। जरा सोचिए कि आप अपने घुटने की सेहत के बारे में बिना डॉक्टर के पास गए, घर बैठे ही जान सकते हैं। और वो भी बिल्कुल सही-सही! ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अब येसच हो रहा है।अशवावियरेबलटेक्नोलॉजीजने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो आपके घुटने की सेहत पर पूरी नजर रखती है। ये डिवाइस हेल्थकेयरसेक्टर में खूब धूम मचा रही है और बहुत ही खास है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियलइंटेलीजेंसका इस्तेमाल किया गया है।ये डिवाइस आपके घुटने के बारे में सारी जानकारी जुटाती है और फिर उस जानकारी को समझकर आपको बताती है कि इस रिपोर्ट में आपके घुटने के बारे में सबकुछ लिखा होता है, जैसे कि आपके घुटने में कोई चोट तो नहीं है, या फिर कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है।अशवा कंपनी की स्थापनाअनमोल अजय सक्सेना ने की है। अनमोल गाजियाबाद की रहने वाली हैं और उन्हेंखुद घुटनों की समस्या थी। अशवा के लिये उन्हें अपने ही अनुभवों से प्रेरणा मिली। अनमोल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और फिजियोथेरेपिस्ट्स के साथ वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के दम पर एक अभिनव समाधान विकसित किया।

महाकुंभ में भगदड़ के बाद इसलिए हो रही.. 2009 बैच के आईएएस अधिकारी की चर्चा

महाकुंभ में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला नाम से अस्थाई जिला स्थापित किया है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2009 बैच के अधिकारी द्रुसंविजय किरण आनंद मेला अधिकारी के रूप में इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़मच गई, जिसमें अभी तक आ रही खबरों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कोई 80 लोग घायल हुए हैं।

महाकुंभ में भगदड़ के बाद महाकुंभ मेला की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएम विजय किरण के नाम की भी चर्चा तेज हो गई है. महाकुंभ मेला की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय किरण आनंद का द्रुसंवनेन तक का सफर बेहद रोचक रहा है. विजय किरण की चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई से यूपीएससी क्लैक करने की कहानी बेहद ही रोचक है.

13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का पर्व अगले महीने 26 फरवरी को छठवे व आखिरी स्नान के साथ समाप्त हो जाएगा. हर दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ संपम स्नान करने के

लिए पहुंच रही है. इस भव्य, दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ आयोजन को संभालने की जिम्मेदारी द्रुसं अधिकारी विजय किरण आनंद के पास है.

द्रुसंके साथ एक योग्य सीए भी हैंविजय किरण विजय किरण आनंद ने साल 2008 संघ लोक सेवा आयोग (क़ष्ट) की सिविल सेवा परीक्षा क्लैक की थी. वह 2009 बैच के यूपी कैडर के द्रुसं अधिकारी हैं. बैंगलुरु में जन्में आईएएस विजय किरण आनंद एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं. विजय किरण ने शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एसडीएम के पद की जिम्मेदारी संभाली थी. बागपत में दो साल तक सेवा देने के बाद उनका ट्रांसफर बाराबंकी कर दिया गया, यहां उन्हें मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात किया गया.

विजय किरण आनंद यूपी के मैनपुरी, उन्नाव, फिरोजाबाद, वाराणसी और शाहजहांपुर में जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं. उन्हें माघ और कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई थी. 2017 में उन्हें माघ मेला और 2019 में अर्ध कुंभ मेला का अधिकारी बनाया गया था. उन्होंने पंचायती राज, सिंचाई और बेसिक शिक्षा जैसे विभागों में भी अपनी

अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोग चालान से बचने के लिए मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। इससे परिवहन विभाग को चालान जारी करने और जुर्माने की वसूली में दिक्कत होती है। अब आधार लिंकिंग से इस समस्या का समाधान करने की योजना बनाई जा रही है।

ड्राइविंग लाइसेंस और RC का पुराना डेटाबेस बना समस्या-

परिवहन विभाग के डेटाबेस में 60, 70 और 90 के दशक की गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनमें से कई में मोबाइल नंबर, आधार लिंक या अपडेटेड पते की जानकारी नहीं है। इससे ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने में परेशानी होती है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है जहां वाहन मालिकों और लाइसेंस धारकों को अपना विवरण अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।

मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा फिल्म में लीड किरदार निभाएंगी



प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल हुई माला बेचने वाली मोनालिसा के हथ अब बॉलीवुड फिल्म आ गई। वे राजकुमार राव के भाई के साथ फिल्म में मेन लीड निभाने जा रही हैं। महाकुंभ में कजरारी आंखों और प्यारी सी मुस्कान के चलते वायरल हुई मोनालिसा अब अपने घर यानी इंदौर के नवदीक

महेश्वर लौट चुकी हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में ही रूक कर रुद्राक्ष माला बेचने वाली थीं, लेकिन 15 दिनों के अंदर ही उन्हें महाकुंभ छोड़ना पड़ा। लेकिन, अब मोनालिसा फिल्म करने जा रही हैं।

मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म में ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ के लिए कास्ट किया है। सनोज मिश्रा उनके गांव गए, जहां मोनालिसा ने उनसे मिलने के बाद फिल्म साइन कर ली है। फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ में मोनालिसा लीड भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सनोज मिश्रा फिल्म्स के बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ के लेखक, निर्माता और निर्देशक सनोज मिश्रा हैं। फिल्म के को-प्रोड्यूसर यामीन खान और जानेद देवरियावाले हैं।

महाकुंभ से अपने घर लौटती मोनालिसा
कुंभ में अचानक इंटरनेट पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने मेले में आने वाले लोगों का ध्यान खींचा। तभी सनोज मिश्रा ने सीच लिया कि मोनालिसा को वह अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे। हालांकि, मोनालिसा को अपना काम छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा था। क्योंकि, वायरल होने के कारण न तो वो माला बेचने का अपना काम ठीक से कर पा रही थी और न ही चैन की सांस ले पा रही थी। लोग उनके आगे-पीछेकैमरा लेकर घूमने लग गए थे।

राजकुमार राव के भाई के साथ काम करेंगी मोनालिसा
हथ डायरेक्टर सनोज मिश्रा इन दिनों फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ की तैयारी में जुटे हैं। ये फिल्म मणिपुर के ज्वलंत मुद्दे पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। सनोज मिश्रा ऐसे डायरेक्टर हैं, जो समाज के ज्वलंत मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं। चाहे उनकी फिल्म ‘काशी टू कश्मीर’ हो या फिर ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ हो, उनकी इस फिल्म का काफी विरोध हुआ था। यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थीं। लेकिन, बिनी इसकी परवाह किए सनोज मिश्रा ने फिल्म रिलीज की और लोगों ने इन्हें खूब पसंद भी किया।

वित्त वर्ष 2025 का केंद्रीय बजट: इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ का ब्लूप्रिन्ट

मुंबई, एजेंसी। जैसा कि हम 2025–26 के केंद्रीय बजट की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर व्यय इकोनॉमी ग्रोथ और विकास का एक प्रमुख चालक होगा। 2024–25 के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 11.1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पहले से ही एक मजबूत आधार तैयार किया है, हम उम्मीद करते हैं किरेलवे, रक्षा, बिजली और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह गति तेज होगी। हालांकि, इन निवेशों की क्षमता को पूरी तरह से समझने के लिए, लक्षित उपाय और प्रोत्साहन जरूरी हैं। आगामी बजट में सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिससे मांग को बढ़ावा देने और लांग टर्म डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिले। सरकार के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है, जिसमें ‘पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसी इनिशिएटिव्स पर विशेष जोर दिया गया है।

महाकुंभ में भगदड़ के बाद इसलिए हो रही.. 2009 बैच के आईएएस अधिकारी की चर्चा

सेवाएं दी. इस साल उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें महाकुंभ 2025 के लिए मुख्य अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है.

महाकुंभ के लिए बनाया अस्थाई जिला

कुंभ मेला 2025 में शामिल होने वालो लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला जिला नाम का एक अस्थायी जिला स्थापित किया. इस जिले में चार तहसीलों के 67 गांव शामिल हैं और इसका प्रशासन द्रुसं अधिकारी विजय किरण आनंद चला रहे हैं जिन्हें यहां का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

बेहतर कार्य के लिए पीएम मोदी ने

किया था सम्मानित

मेला अधिकारी की भूमिका उनके विशाल अनुभव का परिणाम है. उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया और पीएम ने उन्हें स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया था.



सी.एम.ओ पूजा बुनकर सम्मानित, अन्य सी.एम.ओ नाराज



छिंदवाड़ा। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में दमुआ की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर को कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया जिले के सी.एम.ओ ने उन्हें बधाई दी है कई सी.एम.ओ को उम्मीद थी कि उनके कार्यों को देखते हुये उन्हे भी पुरूस्कृत किया जावेगा।

नव नियुक्त कांग्रेस नेत्रियों संतोषी गर्जभिये और सविता कनोजिया का हुआ स्वागत



छिंदवाड़ा – पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 28 जनवरी को सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। इसी क्रम में श्रीमती संतोषी को अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष, श्रीमती सविता कनोजिया को ग्रामीण जिला अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया गया । जब यह जानकारी परासिया विकासखण्ड ग्राम भोईमें लगने पर ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की और दोनों नवनियुक्त नेत्रियों श्रीमती संतोषी गर्जभिये एवं सविता कनोजिया के ग्राम में आमलन पर सर्वप्रथम मंदिर में पूजा अर्चना की एवं रैली निकालकर, डोल बाजों के साथ आरती उताकर, टीका लगाकर, हार मालायें पहनाकर फूलों की वर्षा कर सम्मानित किया गया । इस अवसर पर कार्यकर्ताओं सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे ।

कांग्रेस मनायेगी बापू की पुण्यतिथि
छिंदवाड़ा। आजाद भारत का सपना देखने व उसे साकार करने के लिये निरंतर संघर्ष व आंदोलन कर अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर देश को उनकी गुलामी से आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर कांग्रेस के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम स्थानीय गांधी चौक (फव्वारा चौक) पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसके उपरांत समस्त कांग्रेसजन गांधी गंज पहुंचकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।शहर कांग्रेस के तत्वावधान में आज 30 जनवरी को स्थानीय गांधी चौक (फव्वारा चौक) पर दोपहर 2 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात उनके पिय भजन रघुपति राघवराजा राम का गायन किया जायेगा। महात्मा गांधी चौक के पश्चात समस्त कांग्रेसजन गांधी गंज पहुंचकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस के समस्त विभाग व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर बापू को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन 31 मार्च तक

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन और उपार्जन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार 20 जनवरी 2025 से पंजीयन प्रारंभ हो चुका है जो आगामी 31 मार्च 2025 तक किया जायेगा, जिसमें निर्धारित अवधि में किसान अपना पंजीयन कर सकते है। इस संबंध में जिला आहर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। इसके अलावा पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एम.पी.किसन एप के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया के पूर्व बैंक खाता आधार से लिंक करावें, आधार डाटाबेस में सही मोबाईल नंबर दर्ज कराया जाये, पंजीयन में सही आधार नंबर की प्रविष्टि कराना आवश्यक है।

सीएमओ ने जन्मदिन पर स्कूल के बच्चों को बांटी शैक्षणिक सामग्रियां



बिछुआ। नगर परिषद बिछुआ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष कुमार मेरावी ने अपने जन्मदिन के मौके पर वन गरा माजियापार और पानाथावड़ी के शासकीय स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण किया गया। सीएमओ आशीष कुमार मेरावी की इस अच्छी पहल को समाजसेवियों ने सरहाना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। स्कूल में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते समय निकाय के स्वच्छता निरीक्षक उमम कुमार नरें समेत शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के महाविद्यालयन प्राध्यापक उपस्थित थे।

तामिया के ग्राम हरसदिवारी में मत्स्य उत्पादन का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर
छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की धरती पर महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जिले के विकासखंड तामिया के ग्राम हरसदिवारी के सीएम सरोवर में दुर्गा स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बढ़ाया है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की प्रेरणा और सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार के मार्गदर्शन में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के माध्यम से मत्स्य पालन का नवाचार किया गया है।

महादेव मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने किया पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला का निरीक्षण



छिंदवाड़ा। आगामी महादेव मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह बुधवार को अनुविभाग जुन्नारदेव पहुंचे और सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार के साथ पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला में मंदिर एवं पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम जुन्नारदेव सुश्री कामिनी ठाकुर और सीईओ जनपद पंचायत जुन्नारदेव

सुश्री रश्मि चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के यातायात प्रबंधन से लेकर सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली व्यवस्था आदि के संबंध में समुचित व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा - निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से सुझाव भी लिए। चर्चा के दौरान पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला मंदिर परिसर में निर्मित धर्मशाला के समुचित विकास का सुझाव दिया गया, जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने वन क्षेत्र होने के कारण एसडीएम जुन्नारदेव को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक दावा का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

स्थानीय जनों द्वारा पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला को ट्रस्ट बनाए जाने का भी सुझाव दिया। जिसकी आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने जुन्नारदेव क्षेत्र के विकास को

संबंध में भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की और विभिन्न सुझाव भी दिए। साथ ही आश्चस्त किया कि प्रशासन क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक है, क्षेत्रवासियों की सक्रियता और सहयोग से ही क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित होगा।

शिक्षा का स्तर उत्तम पाए जाने पर कलेक्टर ने निरीक्षण पंजी में दिया रिमार्क



छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने आज सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार के साथ जिले के अनुविभाग जुन्नारदेव के भ्रमण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की कक्षाओं में पहुंचकर उन्हें पढ़ाई जा रहे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण किया। इस दौरान बच्चों की शिक्षा का स्तर उत्तम पाया गया, जिसके लिए कलेक्टर श्री सिंह ने खुशी और संतोष जाहिर करते हुए मौके पर उपस्थित शिक्षिका श्रीमती आरती इवनाती की सरहना की। शाला में एक और शिक्षिका पदस्थ हैं, जो आज अनुमति के बाद आकस्मिक अवकाश पर थीं। बच्चों को हिंदी की अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम का भी ज्ञान होने पर कलेक्टर ने दोनों शिक्षिकाओं द्वारा की जा रही मेहनत की प्रशंसा की और इसी तरह लगन से अध्यापन कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निरीक्षण पंजी में थैंक्स टू टीचर्स रिमार्क दिया। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार और एसडीएम जुन्नारदेव सुश्री कामिनी ठाकुर ने भी अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों के भाषा ज्ञान को परखा। शाला के निरीक्षण के बाद मध्याह्न भोजन के किचेन शेंड और भंडार कक्षा का भी निरीक्षण किया। जहां भी स्थिति संतोषजनक पाई गई। इसके बाद कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम खमारकलां में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया, जिसमें दरवाजा न लगा होने और फिनिशिंग कार्य अधूरा पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ जनपद पंचायत सुश्री रश्मि चौहान और पंचायत का स्थानीय अमला भी मौजूद था।

लगभग 500 मीटर 33 के.व्ही. लाईन की अज्ञात चोरी से तीन सबस्टेशनों की विद्युत सप्लाई बाधित

छिंदवाड़ा। म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 27 जनवरी 2025 को रात्री लगभग 12३0 बजे (संचा/संधा.) पूर्व सभाग म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा के अंतर्गत उमरानाला-द्वितीय 33 के.व्ही. फीडर जो कि 132 के.व्ही. चन्दनगौर से निकलते हुए 33 के.व्ही. सबस्टेशन सरोत कट जाता है। कुल मिलाकर इस फीडर व्दारा 03 सबस्टेशनों से 33 के.व्ही. विद्युत सप्लाई दी जाती है। 33 के.व्ही. उमरानाला, 33 के.व्ही. मउएवं 33 के.व्ही. सरोत जिसमें लगभग 11000 उपभोक्ताओं घरेलू एवं पम्पों को मिलाकर विद्युत सप्लाई की जाती है। इन फीडरों की लगभग 500 मीटर 33 के.व्ही. लाईन को अज्ञात चोरों व्दारा चुरा लिया गया है, जिसके बाद इन तीनों सबस्टेशनों की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है।

कमलनाथ के प्रयासों से ओबीसी वर्ग को मिला सताईस फीसदी आरक्षण का हकः बैजू वर्मा

प्रदेश में पहली दफा तात्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली थी ओबीसी की सुध
भाजपा सरकार के सारे षड्यंत्र हुए विफल, नाथ के निर्णाय को उच्च न्यायालय ने भी ठहराया उचित पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी शासकीय भर्तियों में इस तत्काल लागू करने सीएम से किया आग्रह

छिंदवाड़ा। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अथक प्रयासों से ओबीसी वर्ग को उनकी मंशानुसार शासकीय भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। मप्र में पहली दफा कमलनाथ सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग को शासकीय भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया था जिसके उपरांत ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार ने विभिन्न माध्यमों से षड्यंत्र कर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखने की भरपूर कोशिशें की, किन्तु अंत में जीत सच्चाई की हुई। उक्त उदगार आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जिलाध्यक्ष बैजू वर्मा ने व्यक्त किए हैं। श्री बैजू वर्मा ने जारी बयान में आगे कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कमलनाथ ने मार्च 2019 में प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया था। दिनांक 19 मार्च 2019 को उच्च न्यायालय ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल विषयों के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया, किन्तु यह स्थान केवल कुछ नौकरियों के लिए था। इसके उपरांत ओबीसी के रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में कमलनाथ सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास किया था। किन्तु भाजपा ने षड्यंत्र कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी और फिर तात्कालीन सीएम श्री कमलनाथ द्वारा ओबीसी वर्ग के हित में लिए गए आरक्षण सम्बंधित फैसलें में षड्यंत्रकारी रूख अपनाते हुए उसमें अनेकों-अनेक पेचीदियां लगाई गईं। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। विगत 6 वर्षों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो

यह बात स्पष्ट हो जाती है।

वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं को सौंपे
अहम जिम्मेदारीः नकुलनाथ
संगठन से पहले आप मेरी शक्ति है जिससे मुझे
बल मिलता हैः कमलनाथ

छिंदवाड़ा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी की नौव है। उनकी कार्यकुशलता, अनुभव व समर्पण का लाभ युवा पीढ़ी को मिलाना चाहिए। नई नियुक्तियों के लिए भरपूर समय है इसीलिये जिम्मेदारी सौंपते समय संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता की मंश को भी जानें साथ ही नई नियुक्तियों में युवाओं को मौका मिले इस पर

विशेष ध्यान दिया जावे। उक्त उदगार आज पूर्व सांसद श्री नकुलनाथ ने विधानसभा प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रभारी, पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त शहर अध्यक्ष, समन्वयक, कार्यकारी अध्यक्ष व मोर्चा संगठन के जिलाध्यक्षों की आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। नकुलनाथ ने शिकारपुर कमलकुंज में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि नई नियुक्तियों के लिए भरपूर समय है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं को मौका मिले इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के लोग स्वयं डबल व तीन डीजन वाली सरकार से विकास की बात करते हैं, किन्तु विगत 7 माह में छिंदवाड़ा व पाहुर्ना जिले में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए, यह बात आम जनता तक पहुंचाना होगा। आमजन को यह समझना होगा कि भाजपा किस तरह झूठ बोलकर वोट मांगती है, चुनाव जीतने के बाद अपने वायदें भूल जाती है, इसके अनेक उदाहरण आप सभी के पास है इसीलिये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षक नैतिकतापूर्ण, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें



छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय महाहानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल एवं जिला परियोजना समन्वयक जे.के.इंडपाचे के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के समूचे अमले में 99 जनशिक्षा केंद्रों के जनशिक्षक एवं 11 विकासखंड के समस्त बी.ए.सी, एम.आर.सी.बी.आर.सी. की मंत्रावन बैठक ली गई। बोर्ड परीक्षा के निकट दृष्टित बैठक में 11 बजें से लेकर 5 बजे तक जनशिक्षको एवं बीएसी को बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु मार्गदर्शित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने कहा कि शिक्षक नैतिकतापूर्ण, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें शिक्षकों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अमर्यादित व्यवहार क्षम्य नहीं होगा। उन्होंने जनशिक्षकों को निर्देशित किया कि वह अपने जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर लापरवाह शिक्षकों की जानकारी बीआरसी के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध करावे साथ ही गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य के साथ उत्कृष्ट एवं प्रसशनीय कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम भी प्रेषित करें, जिससे कि जिला स्तर पर ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए जिला परियोजना समन्वयक जे.के.इंडपाचे ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग की समस्त प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का केंद्र बिंदु जनशिक्षक ही

है।जनशिक्षक अपने पदीय दायित्व के अनुरूप अकादमिक मॉनिटरिंग के साथ-साथ शासन की समस्त योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में एजेंडे के अनुसार ए.पी.सी. संकेत जैन द्वारा अकादमिक एजेंडे पर समस्त शासकीय शालाओं में एफ.एल.एन. अंतर्गत चल रही गतिविधियों, आवधिक आंकलन के आधार पर विद्यालय को ए.बी. सी.डी ग्रेडवार चिन्हांकित किया जाना, कक्षा पांचवी एवं आठवीं के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, परीक्षा केंद्र एवं केंद्र अध्यक्ष के प्रस्ताव, एंडलाइन की पूर्ण तैयारी, आठवीं एवं पांचवी अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तों की प्रविष्टि आदि विषयों पर सूक्ष्मता से विकासखंडवार एवं जनशिक्षा केंद्र वार ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदाय किए गए।एपीसी मुकेश श्रीवास्तव द्वारा ई.एंड आर अंतर्गत यू डाइस पोर्टल पर नामांकन, चालूस्तर प्रगति की एट्री, मैपिंग नहीं किए जाने वाले छात्रों की संख्या, ड्रॉपबॉक्स,ड्रॉप आउट छात्रों से संबंधित जानकारी की समीक्षा की गई।वहीं ए.पी.सी. मथुरा प्रसाद चौरिया द्वारा आई ई डी अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के चिह्नकन एवं यू डाइस पोर्टल पर छात्री प्रविष्टि, विकासखंड स्तर पर संसाधन कार्य के मॉनिटरिंग के साथ होम बेसड एजुकेशन वाले बच्चों से एम. आर.सी. द्वारा भेंट करने संबंधी मॉनिटरिंग प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।

शेषराव यादव को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने पर दी बधाई



अमरवाड़ा। अमरवाड़ा विकासखंड यादव महासभा के सामाजिक बंधुओं के द्वारा यादव समाज के गौरव पूर्व उपाध्यक्ष महाकौशल विकास शेषराव यादव को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके निवास पहुंचकर उन्हे पुष्प गुच्छ भेंट कर समाज की ओर से सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित किये। जिसमें मुकेश यादव यादव महासभा के विकासखंड के अध्यक्ष, शालिग्राम यादव अध्यक्ष नगर यादव महासभा, संजय यादव अध्यक्ष युवक यादव महासभा, अजय यादव कोषअध्यक्ष नगर यादव महासभा, लक्ष्मण यादव, संतोष यादव, राजकुमार यादव, दीपक यादव, अरविंद यादव, विजय यादव एवं समाज के सभी बंधुवर उपस्थित रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 08 फरवरी को

छिंदवाड़ा। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉ.सी.एस.पानकर ने बताया कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 08 फरवरी 2025 शनिवार को प्रातः 11३० बजे से दोपहर 01.30 बजे तक 7 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जायेगी। प्रवेश परीक्षा- 2025 के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने जिले के कक्षा 8वीं एवं 10वीं के सभी पंजीकृत विद्यार्थियों से नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट एवं https:// cbseitms. nic.in/wowny/nvsi&/ से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी है। परीक्षा के समय प्रत्येक अभ्यर्थी मूल प्रवेश पत्र एवं मूल आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र में आयेगे।

दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के निःशुल्क उपकरण हेतु पंजीयन शिविर 30 को

छिंदवाड़ा। आधार फाउंडेशन एवं सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा नगर के परिसर्या रोड स्थित दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों के लिए जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदाय करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन आज गुरुवार 30 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक मुख्य अतिथि डॉक्टर शेषराव यादव जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती गरिमा प्रकाश दामोदर एवं कार्यक्रम अध्यक्ष सर्वोदय के प्रदेश संयोजक नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर दीपक राज जैन की उपस्थिति में किया गया है। जिसमें सभी वृद्धजनों सहित दिव्यांगजनों से सम्मिलित होकर शिविर का लाभ लेने की अपील समेत के जिला सह संयोजक इंजी. महेश किंथ एवं आधार फाउंडेशन की संचालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता पांडे द्वारा की गई है।

प्राथमिक शिक्षक निलंबित

छिंदवाड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी जी.एस.बघेल द्वारा विकासखंड मोहखेड़ के शासकीय प्राथमिक शाला बाड़ीवाड़ा संकुल केन्द्र सांवरीबाजार के प्राथमिक शिक्षक श्री तुकाराम गौतम को गणतंत्र दिवस की पूर्व संस्था पर शाला में अन्य बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर शराब का सेवन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहखेड़ के 28 जनवरी 2025 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विकासखंड मोहखेड़ के शासकीय प्राथमिक शाला बाड़ीवाड़ा संकुल केन्द्र सांवरीबाजार के प्राथमिक शिक्षक श्री तुकाराम गौतम के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संस्था पर शाला में अन्य बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर शराब का सेवन किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आचरण नियमों के तहत कोई भी शासकीय सेवक अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा और न ही उसके प्रभाव में रहेगा। जिला मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्राथमिक शिक्षक श्री गौतम के द्वारा अपने कर्तव्यस्थल पर मादक पेय पदार्थों का प्रयोग करना प्रदर्शित हो रहा है, जो अनुशासनहीनता एवं शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत है।

अरुन धुर्वे को युवक कांग्रेस पाहुर्ना विधानसभा प्रभारी

पाहुर्ना व सौसर युवक कांग्रेस में हुई नवनियुक्तियां

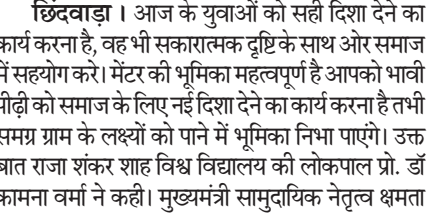
छिंदवाड़ा। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार पाहुर्ना विधानसभा युवक कांग्रेस व सौसर ब्लॉक, बड़चिचोली व नांदनवाड़ी ब्लॉक युवक कांग्रेस में नवनियुक्तियां की गई है। पाहुर्ना जिला प्रभारी गंगाप्रसाद तिवारी पाहुर्ना जिला अध्यक्ष सुरेश बल्लक, मोर्चा संगठन के प्रभारी आनंद बक्षी, पाहुर्ना विधायक निलेश उखें व सौसर विधायक विजय चौर की सहमति लेकर पंकज दातारकर जिला युवक कांग्रेस प्रभारी पाहुर्ना एवं जिला युवक कांग्रेस पाहुर्ना अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गांवडे के द्वारा नई नियुक्तियां की गई है जो निम्नानुसार है। अरुन धुर्वे को युवक कांग्रेस पाहुर्ना विधानसभा प्रभारी, बंटी ठाकुर अध्यक्ष युवक कांग्रेस पाहुर्ना विधानसभा, पाहुर्ना विधानसभा में कार्य. अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चेतन साहू व निलेश कोडपे को सौंपी है। बड़चिचोली ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष रजत पाराङकर व कार्य. अध्यक्ष विकास पाराङकर एवं रोशन कुमरे मनोनीत किए गए है। मारूड ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष चैतराम चौधरी व कार्य. अध्यक्ष कृष्णाराव राउत, प्रभारी द्विेश ठाकूर मनोनीत किए गए है। प्रदीप उखे को नांदनवाड़ी ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

सौसर युवक कांग्रेस में हुई नियुक्तियां

सौसर युवक कांग्रेस विधानसभा व सौसर ब्लॉक युवक कांग्रेस में नवनियुक्तियां की गई है। डॉ. शिव सालोकर को प्रभारी युवक कांग्रेस विधानसभा सौसर, राजा बोडे को अध्यक्ष युवक कांग्रेस विधानसभा सौसर, संदीप ठाकरे को प्रभारी ब्लॉक युवक कांग्रेस सौसर व हर्षल पिंगले को अध्यक्ष ब्लॉक युवक कांग्रेस सौसर मनोनीत किया गया है।

युवाओं को सही दिशा प्रदान करे मेंटरः श्रीमती डॉ कामना वर्मा

जनअभियान परिषद के मेंटर्स का दो दिवसीय मेंटर प्रशिक्षण आरंभ



छिंदवाड़ा । आज के युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करना है, वह भी सकारात्मक दृष्टि के साथ और समाज में सहयोग करें। मेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है आपको भावी पीढ़ी को समाज के लिए नई दिशा देने का कार्य करना है तभी समस्या ग्राम के लक्ष्यों को पाने में भूमिका निभा पाएंगे। उक्त बात राजा शंकर शाह विश्व विद्यालय की लोकपाल प्रो. डॉ कामना वर्मा ने कही। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतगत परामर्शदाताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण में बोल रही थीं। इस अवसर पर डॉ पी सनेसर प्रोफेसर, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद अखिलेश जैन, नैनसुख ग्राम विकास के संभाग थयोजक, मनीषा यादव ट्रेनर सीआईआई, समस्त विकासखंड समन्वयक, सभी परामर्श दाता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी परामर्श दाता विनोद तिवारी, आभार प्रदर्शन जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने किया। भातमाता के चित्र पर माल्यार्पण एवम् दीप प्रज्वलित कर

कार्यक्रम का शुभारंभ उपरांत श्रीमती कामना वर्मा ने कहा जन अभियान परिषद प्रारंभ से स्वेच्छिक आधार पर समाज में अनुकरणीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर समग्र विकास के लिए कार्य करता रहा है, इस प्रकार के प्रशिक्षण से कार्यो को और अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करना है वह भी सकारात्मक दृष्टि के साथ देश के विकास के सहयोग करें। मेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है आपको भावी पीढ़ी को गढ़ने का कार्य करना है तभी समस्या ग्राम के लक्ष्यों को पाने में भूमिका निभा पाएंगे। प्रोफेसर पी सनेसर ने सोशल लीडरशीप को विस्तार से समझाया और उन्होंने मेंटर की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जन अभियान के कार्यो के बारे में रोचकता के साथ मेंटर को बताया। जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने ने समाज कार्य की अवधारणा और कोर्स में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने जन अभियान की बात अवधारणा की बात बताई, जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि जन अभियान परिषद के मेंटर्स अपनी क्षमता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें, इसके लिये सामुदायिक नेतृत्व पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ मिलकर शासन के विभागों से समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें तभी जन अभियान परिषद और आपके कार्यो की सार्थकता सिद्ध होती है। उन्होंने जन अभियान परिषद के कार्यो को विस्तृत रूप से समझाया।





भोपाल। विश्व वेटलैंड दिवस पर बोट क्लब पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भोपाल में वेटिंग शिक्षकों की दंडवत
पद यात्रा, महिलाएं कराएंगी मुंडन

भोपाल। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-1 2023 में महिला शक्ति द्वारा महाआंदोलन की जा रहा है। यात्रा की शुरुआत भोपाल के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सीएम हाउस तक दंडवत यात्रा सुबह 11 बजे होगी। जिसके बाद सामूहिक रूप से महिला मंडन भी करवाएंगी।



इसके अलावा पुरुष अर्थाथी रानी कमलपति स्टेशन से वीआईआई तक डेवत यात्रा निकालेंगे। अर्थाथीयों की माने तो सरकार रिकत पदों में पद वृद्धि करके 2 काउंसिलिंग के लिए लिखित आवासन नहीं देती है। इस लिए सरकार रिकत पदों में पद वृद्धि करके 2 काउंसिलिंग करे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 1 2023 में रिक्त पदों की जानकारी गण्ट पत्र श्रृङ्ख 27 दिसंबर 2024 के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में लगभा 15000 से अधिक पद रिक्त हैं। जिसमें सरकार रिकत पड़े पदों में पद वृद्धि करके 2 काउंसिलिंग करे।

आखिरकार इंदौर के भी बीजेपी जिलाध्यक्ष घोषित

**सुमित मिश्रा बने शहर अध्यक्ष, श्रवण सिंह चावड़ा
को मिली ग्रामीण की कमान**



बीजेपी ने इंदौर नगर में सुमित मिश्रा और इंदौर ग्रामीणों में श्रवण सिंह चावड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया है। आज सुबह ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की थी। वे कृषिभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में स्थित बापू की श्रद्धांजलि समारोह में वीडियो भाग के साथ शामिल हुए थे। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के चुनाव को रायसुमारी की प्रक्रिया दिखाने में ही पूरी कर ली थी। लेकिन नेताओं के बीच आपसी खींचतान के चलते जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करने में 12 दिन का वक़्त लग गया। 12 जनवरी को बीजेपी ने सिर्फ दो जिलों— उज्जैन और विदिशा जिला अध्यक्ष घोषित करके शुरुआत की थी।



बापू की पुण्यतिथि पर बीजेपी-कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जुटे नेता, सीएम ने जापान में बापू को याद किया

भोपाल। महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर सरकार आज प्रदेश भर में शहीद दिवस का आयोजन कर रही है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम राजनैतिक दल बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जापान के कोबे शहर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित कर बापू को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन भारतीयों के लिए समर्पित रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में ठीक ही कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को

इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।

इधर, भोपाल के कुशाभाऊ ठकुरे सभागार परिसर में लगी बापू की प्रतिमा पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंत्री तुलसी सिलावत, विधायक भगवानदास सबनानी, रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव की मौजूदगी में बापू को श्रद्धांजलि दी।

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किया।



कर्मचारियों ने 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा

मंत्रालय के सामने पार्क में मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में बापू को दी गई। श्रद्धांजलि ठीक 11 बजे सायरन बजाने के साथ ही मौन शुरू हुआ और 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद बापू को पुष्पांजलि देने के बाद अधिकारी कर्मचारी अपने काम के लिए खाना हो गए।

कांग्रेस ने प्रदेश भर में रखे कार्यक्रम

बापू की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिला, शहर कांग्रेस कमिटीयों को महान्ता गांधी की पुण्यतिथि पर जिला अस्पतालनों में मरीजों को फल वितरण, संगे और सभी धर्म सम भा आदि कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महान्ता गांधी जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। कार्यक्रम में जिलों के वरिष्ठ कांग्रेसजनों, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, कांग्रेस पथ के स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकाशों के पदाधिकारियों समेत अन्य सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

हाईकोर्ट ने पूछा- कहां है 84 करोड़ के उपकरण

**स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के खिलाफ याचिका
दायर; 2016 में मिले थे 135 करोड़**

जबलपुर। मध्य प्रदेश स्टेट कैसर इंस्टीट्यूट में अभी तक 84 करोड़ से अधिक रुपए के उपकरण खरीदे नहीं है। लेकिन कैसर मशीनों को अभी भी राहत नहीं है, लिहाजा इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि स्टेट कैसर इंस्टीट्यूट के कैसर वार्ड के 2016 में स्वीकृत 84 करोड़ रुपए से अभी तक कौन-कौन से उपकरण खरीदे गए हैं।

कोर्ट ने सरकार व कैसर संस्थान को

रहा है।

एडवोकेट विकास मखरन ने कोर्ट का बताया कि केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए का बजट स्टेट कैस रीडिस्ट्र्यूट के लिए आवंटित किया था। इसमें से कर बजट 50 करोड़ रुपए में बिल्डिंग तैयार करने की गई। याचिका में यह भी बताया गया कि मरीजों को के अभाव में संस्थान का उचित रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। मरीजों को रेडिऐशन थेरेपी का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं।



अतिरिक्त हलफनामा पेश करने को कहा है। जबलपुर निवासी एडवोकेट विकास महावर की ओर से हाई कोर्ट में स्टेट कैन्सर इंस्टीट्यूट को लेकर याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता ने हार्ड कोर्ट को बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंडिकटल कॉलेज में प्रदेश का एकमात्र स्टेट कैम्पस इंस्टीट्यूट है, जहां पर की न सिर्फ जवाबपुर बल्कि समूचे महाराष्ट्र, बुंदेलखंड से कैम्पस मरीज इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। करीब 8 साल पहले 2016 में कैम्पस इंस्टीट्यूट की सौगात मिली थी, लेकिन आज भी कैम्पस से पीछड़ा गंभीर मरीजों को इंस्टीट्यूट में इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परेशान होकर उन्हें बड़े शहरों में जाकर महंगा इलाज करना पड़

मशीनों के लिए राज्य सरकार के पास करीब 84 करोड़ रुपए पड़े हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीनेश कुमार केथर और जस्टिस निवेक जैन को उरीजिन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि स्टेट कैसर इस्टीमेट के कैसर वार्ड के 2016 में स्वीकृत 84 करोड़ रुपये से अंधी तक नौकन-नौकन से उपकरण खरीदे जा रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि 8 वर्ष पूर्व राशि स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक संस्था में उपकरण क्यों नहीं खरीदे गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की गई है।

सीआरपीएफ जवान ने पत्नी को गोली मारकर आत्महत्या की, कमरे में मिले दोनों शव

भोपाल। भोपाल के बंगरसिया स्थित कालीनी में रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने बुधवार-गुरुवार दरमियानी रात 1.30 बजे गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। उसने पत्नी को दो से ज्यादा गोलियां मारी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 100 में खुद काल कर हत्या करने की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो जवान का शव खून से लथपथ मिला। पास ही पत्नी का शव भी पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों बाँड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को पास ही पड़ी सर्विस इंसास राइफल और आठ कारतूस मिले हैं।

पुलिस पहुंची तो पति-पत्नी के लहलुहान शव मिले- टीआई मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि रात करीब 1२30 बजे रविकांत ने कॉल कर बताया कि मैंने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। फिलहाल



ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों को कितनी गोली लगी है। पत्नी की बाँडी में पीएम और पसली पर दो घाव साफ दिख रहे हैं। दोनों बाँडी का पीएम एम्स कराया जा रहा है।

रविकांत वर्मा (35) और पत
रेनू वर्मा (32) सीआरपीएफ कैप
पास सिविल कॉलोनी में रहते थे।
लोग मूल रूप से भिंड के मिहोना
रहने वाले थे। जानकारी के मुताबि

इनके दो बच्चे ढाई साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। रविकांत के दो अन्य भाई भी सीआरपीएफ में ही नौकरी करते हैं। रवि 13 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था।

दूसरे कमरे में बिलखते मिले
दंपती के दोनों बच्चे

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी के शव एक कमरे में थे, जबकि दोनों मासूम दूसरे कमरे में बैठे बिलख रहे थे। गोलियों की आवाज सुनने के बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक पत्नी-पत्नी की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े की आवाज आती थी।

मायके को ज्यादा तबज्जो देने को लेकर विवाद

पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि सीआरपीएफ जावन रिवकांत और रेनु की 8 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस रेनु मयवने पक्ष से फोन पर ज्यादा बातचीत करती थी। जवान को लगता था कि पुलिस सगुराला से कदाभी पक्ष को नजरबन्दी देती है। उससे और बच्चों से ज्यादा समय फोन पर बातचीत में बिताती है। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होते थे। पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच हुआ विवाद दार तक रक्त चला, इसने बड़ा जवान ने यह करद करद उठाया।